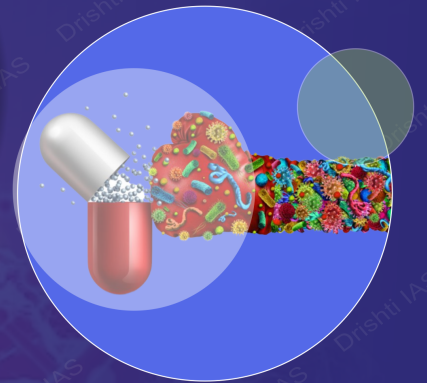


रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AntiMicrobial Resistance-AMR)

सूक्ष्मजीवों में रोगाणुरोधी दवाओं के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता



Drishti IAS



AMR में वृद्धि के कारण

- संक्रमण नियंत्रण/स्वच्छता की खराब स्थिति
- एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग
- सूक्ष्मजीवों का आनुवंशिक उत्परिवर्तन
- नई रोगाणुरोधी दवाओं के अनुसंधान एवं विकास में निवेश का अभाव

AMR विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को 'सुपरबग' कहा जाता है

AMR के प्रभाव

- ↑ संक्रमण फैलने का खतरा
- संक्रमण को इलाज को कठिन बना देता है; लंबे समय तक चलने वाली बीमारी
- ↑ स्वास्थ्य सेवाओं की लागत

उदाहरण

- K निमोनिया में AMR के कारण कार्बापेनेम (Carbapenem) एंटीबायोटिक्स प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं
- AMR माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी (RR-टीबी) का कारण बनता है
- दवा प्रतिरोधी HIV (HIVDR) एंटीरेट्रोवाइरल (ARV) दवाओं को अप्रभावी बना रहा है

WHO द्वारा मान्यता

- AMR की पहचान वैश्विक स्वास्थ्य के लिये शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में
- वर्ष 2015 में GLASS (ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम) लॉन्च किया गया

AMR के खिलाफ भारत की पहलें

- टीबी, वेक्टर जनित रोग, एड्स आदि का कारण बनने वाले रोगाणुओं में AMR की निगरानी।
- वन हेल्थ के दृष्टिकोण के साथ AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2017)
- ICMR द्वारा एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम

न्यू देल्ही मेटालो-बीटा-लैक्टामेज़-1 (NDM-1) एक जीवाणु एंजाइम है, जिसका उद्भव भारत से हुआ है, यह सभी मौजूदा β -लैक्टम एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय कर देता है

वर्षेष् श्रेणी का दरजा

प्रलिमिन्स के लललल:

वर्षेष् श्रेणी के राज्य, गाडगलल सूतुर

मेन्स के लललल:

वर्षेष् श्रेणी की स्थतललल से जुडे लाभ और मुददे

चरचा में क्यौं?

हाल ही में केंद्रीय वतलतल मंतुरी ने स्पष्ट कलल ककेंदर कसी भी राज्य के ललल 'वर्षेष् श्रेणी के दरजे' की मांग पर वचलर नहीं करेगा क्यौंकल 14वें वतलतल आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कवलषेष् दरजा नहीं दलल जा सकतल है ।

- यह ओडशल, बहलर, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के ललल बड़ा झटका है क्यौंकल ये राज्य पछले कुछ वर्षों से वर्षेष् श्रेणी के दरजे की मांग कर रहे हैं ।

वर्षेष् श्रेणी का दरजा (SCS):

■ परचलल:

- वर्षेष् श्रेणी का दरजा (SCS) केंदर दवलरल नरलधलरतल उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलकल और सामाजकल-आर्थकल नुकसान का सामना करते हैं ।
- संवधलन SCS के ललल प्रलवधलन नहीं करतल है और यह वर्गीकरण बाद में 1969 में पाँचवें वतलतल आयोग की सफलरशलों के आधार पर कलल गलल था ।
- पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड को यह दरजा दलल गलल था ।
- पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय वकलस परषलद दवलरल योजना के तहत सहायतल के ललल SCS प्रदान कलल गलल था ।
- असम, नगालैंड, हमाचल प्रदेश, मणपुर, मेघालय, सकलकमल, तुरपुरल, अरुणाचल प्रदेश, मज़ोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहतल 11 राज्यों को वर्षेष् श्रेणी का दरजा दलल गलल ।
 - तेलंगाना, भारत के सबसे नवीन राज्य को यह दरजा दलल गलल था क्यौंकल इसे आंध्र प्रदेश राज्य से अलग कलल गलल था ।
- 14वें वतलतल आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के ललल 'वर्षेष् श्रेणी का दरजा' समाप्त कर दलल है ।
 - इसने सुझाव दलल कल प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को 'कर हस्तांतरण' के माध्यम से भरा जाए, केंदर से कर राजस्व में राज्यों की हसलसेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह कलल गलल है ।
- SCS, वर्षेष् स्थतललल से अलग है जो बढ़े हुए वधलयी और राजनीतकल अधकलर प्रदान करती है, जबकल वर्षेष् श्रेणी का दरजा (SCS) केवल आर्थकल और वतलतीय पहलुओं से संबंधतल है ।
 - उदाहरण के ललल अनुच्छेद 370 के नरलस्त होने से पहले जम्मू-कश्मीर को वर्षेष् दरजा प्राप्त था ।

■ नरलधलरक (गाडगलल सफलरशल पर आधारतल):

- पहाड़ी इलाका
- कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हसलस
- पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरकल स्थतलल
- आर्थकल और आधारभूत संरचना पछलड़ापन
- राज्य के वतलतल की अव्यवहार्य प्रकृतल

वर्षेष् श्रेणी के दरजे के लाभ:

- अन्य राज्यों के मामले में 60% या 75% की तुलना में केंदर प्रललोजतल योजना में आवश्यक नधलकल 90% वर्षेष् श्रेणी के राज्यों को भुगतान कलल जलतल है, जबकल शेष नधलकल राज्य सरकारों दवलरल प्रदान की जलती है ।
- वतलतीय वर्ष में अव्ययतल नधलव्यपगत नहीं होती है और इसे आगे बढ़लल जलतल है ।
- इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं नगलम कर में महत्त्वपूर्ण रलललतें प्रदान की जलती हैं ।
- केंदर के सकल बजट का 30% वर्षेष् श्रेणी के राज्यों को प्रदान कलल जलतल है ।

वर्षेष् श्रेणी के दरजे के संबंध में चतललः

- यह केंद्रीय वित्त पर दबाव में वृद्धि करता है।
- साथ ही एक राज्य को वशिष दर्जा देने से दूसरे राज्य भी ऐसी मांग करने लगते हैं। उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार द्वारा की जाने वाली मांग।

नबिकरष:

- जैसा कि 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था, राज्यों को कर हस्तांतरण बढ़ाकर 42% कर दिया गया है और इसे [15वें वित्त आयोग \(41%\)](#) द्वारा भी जारी रखा गया है ताकि SCS का वसितार कयि बनिा संसाधन भनिनता/अंतर को कम कयिा जा सके।

सरोत: द हदुि

ग्रामीण पर्यटन

परलिमिस के लयि:

ग्रामीण पर्यटन, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय वरिसत स्थल, ग्राम समूह, भारत भ्रमण 2023।

मेन्स के लयि:

ग्रामीण पर्यटन, महत्त्व और चुनौतियाँ।

चरचा में क्यौं?

पर्यटन मंत्रालय के ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे (CNA- RT & RH) प्रभाग ने ग्रामीण भारत में आने के इच्छुक पर्यटकों हेतु वशिषिट क्षेत्रों की पहचान की है, जनिमें कृषिपर्यटन, कला एवं संस्कृति, [इकोटूरजिड](#), वन्य जीवन, जनजातीय पर्यटन तथा होमस्टे शामिल हैं।

- पर्यटन मंत्रालय प्रतस्पर्द्धी और स्थायी तथा ज़मिमेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य मूल्यांकन एवं रैंकिग मानदंड स्थापति करने पर भी काम कर रहा है।

परमुख बडुि

- उद्देश्य:
 - इस पहल का उद्देश्य बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के विकास के बजाय धारणीय विकास पर ज़ोर देना है।
 - इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों तथा गाँवों में रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देकर समुदायों को अद्वितीय जैवकि अनुभव प्रदान करना है।
 - पर्यटन मंत्रालय बजट तैयार करने की प्रक्रिया में है, जसिमें ज़िला स्तर पर कुछ प्रशकिषण मॉड्यूलस 100% केंद्र द्वारा वतितपोषति कयि जाऐंगे, जबकि अन्य मामलों में 60% केंद्र और 40% राज्य द्वारा वतितपोषति होंगे।
- ग्राम समूह:
 - लगभग पाँच से सात गाँवों के समूह/क्लस्टर चहिनति कयि जाऐंगे।
 - ये क्लस्टर लंबी दूरी के साथ अलग-अलग गाँवों की ग्रामीण पर्यटन परयोजनाओं की तुलना में पर्यटकों को अधिक आकर्षति करेंगे।
 - ये शलिप बाज़ारों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के वपिणन में ग्राम समूह को सहायता प्रदान करेंगे।

ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा:

- परिचय:
 - भारत में ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण जीवन-शैली और संस्कृति की खोज तथा अनुभव पर केंद्रति है।
 - इसमें स्थानीय संस्कृति और जीवन के प्रतगिहरी समझ वकिसति करने के लयिग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करना और खेती, हस्तशलिप एवं गाँव की सैर जैसी वभिनिन गतविधियों में भाग लेना शामिल है।
 - उदाहरण के लयि तमलिनाडु का कोलुककुमलाई वशिष का सबसे ऊँचा चाय बागान है; केरल में देवलोकम नदी के कनारे एक योग केंद्र है; नगालैंड का कोन्याक टी रटिरीट आदि आगंतुकों/पर्यटकों को आदवासी संस्कृति को समझने-जानने में मदद

करते हैं।

- **वसितार:**
 - भारत की ग्रामीण पर्यटन क्षमता इसकी **वविधि और जीवंत संस्कृति, हस्तशिल्प, लोक कलाओं, त्योहारों और मेलों में** नहिती है।
 - एक अमेरिकी मार्केट रिसर्च कंपनी, **ग्रैंड व्यू रिसर्च** के अनुसार, **कृषि-पर्यटन उद्योग वर्ष 2022 से 2030 तक 11.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर (CAGR) से बढ़ने की संभावना है।**
- **महत्त्व:**
 - **ग्रामीण पर्यटन न केवल स्थानीय कला और शिल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ व्यवहार्य पारंपरिक व्यवसायों को वसिथापति होने से रोक सकता है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्विकास एवं ग्रामीण जीवन को पुनः जीवंत करने, रोजगार तथा नए व्यावसायिक अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा।**
- **लाभ:**
 - बाह्य-प्रवासन में कमी, वैकल्पिक व्यापार के अवसरों में वृद्धि
 - उद्यमशीलता के दायरे में वृद्धि
 - गरीबी उन्मूलन में मदद
 - सामुदायिक सशक्तीकरण
 - कला और शिल्प
 - वरिसत संरक्षण

भारत में ग्रामीण पर्यटन के लिये चुनौतियाँ:

- **बुनियादी ढाँचे की कमी:**
 - ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर **अच्छी सड़कों, बजिली और स्वास्थ्य सुविधाओं** जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, इसे पर्यटकों को आकर्षित करने की दशा में एक बाधा के रूप में देखा जाता है।
 - अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा भी आगंतुकों/पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने की स्थानीय समुदायों की क्षमता को कम कर सकता है।
- **जागरूकता की कमी:**
 - पर्यटकों और स्थानीय समुदायों के बीच ग्रामीण पर्यटन के बारे में जागरूकता की कमी पर्यटन क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
 - बड़ी संख्या में लोग पर्यटन स्थलों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता और पर्यटन से स्थानीय समुदायों को होने वाले लाभों से अनजान हैं।
- **नमिन आय और बेरोज़गारी:**
 - ग्रामीण क्षेत्र अधिकांशतः **नमिन-आय स्तर और उच्च बेरोज़गारी दर** से पीड़ित होते हैं।
 - इससे स्थानीय समुदायों के लिये पर्यटन के बुनियादी ढाँचे में निवेश करना और आगंतुकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करना मुश्किल हो सकता है।
- **पारस्थितिकी के लिये खतरा:**
 - यदि इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया, तो ग्रामीण पर्यटन में **स्थानीय समुदायों और पर्यावरण को नुकसान** होने की संभावना है।
 - भीड़भाड़, प्रदूषण और प्राकृतिक आवासों का वनाश स्थानीय पारस्थितिकी तथा संस्कृतिको नुकसान पहुँचा सकता है, जो लंबे समय तक आगंतुकों को यहाँ आने से रोक सकता है।
- **सुरक्षा चिंताएँ:**
 - **उचित सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण** पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जिससे पर्यटन अनुभव और गंतव्य के प्रतानिकारात्मक छवि बन जाती है।

संबंधित पहल:

- सरकार ग्रामीण पर्यटन स्थलों के रूप में विकास के लिये **परंपरागत कृषिविकास योजना (PKVY)** और **मशिन ऑरगेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCD-NER)** के तहत विकसित जैविक कृषि क्षेत्रों की खोज कर रही है।
- देश भर से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का चयन करने और देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हाल ही में **मैस्ट टूरिज़्म वलैज कॉम्पटिशन पोर्टल** लॉन्च किया गया।
 - 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता' तीन चरणों में आयोजित की जाएगी और इसके लिये ज़िला स्तर, राज्य स्तर और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रवर्षितियों मांगी जाएगी।
- पर्यटन मंत्रालय ने देश की **वभिनिन पर्यटन पेशकशों को उजागर करने और उन्हें वैश्विक पर्यटकों के सामने प्रदर्शित करने के लिये** भारत में आने वाले यात्रियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **वज़िटि इंडिया ईयर- 2023** की शुरुआत की है।
- **'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक वरिसत संवर्द्धन अभियान' (National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive- PRASHAD)** को पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
 - अभी तक प्रसाद (PRASHAD) योजना के तहत 1586.10 करोड़ रुपए की कुल 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
- वर्ष 2014-15 में आरंभ **सुवदेश दर्शन योजना** देश में थीम-आधारित पर्यटन सर्कटि के एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
 - थीम- इको, हेरिटेज, हिमालयन एवं तटीय सर्कटि आदि जैसे वभिनिन वषियों के तहत 5315.59 करोड़ रुपए की राशिके साथ 76 परियोजनाएँ मंजूर की गई थीं।

आगे की राह

- ग्रामीण पर्यटन स्थल बशिष्ट रूप से उन क्षेत्रों के नज़दीक होने चाहिये जहाँ लोग आमतौर पर आवागमन करते हैं।
- ग्रामीण पर्यटन के लिये वकिसति किये जाने वाले गंतव्यों के चयन हेतु गंतव्यों तक पहुँच पहला मानदंड होना चाहिये।
- गंतव्यों का प्रचार-प्रसार कारीगरों को अपने उत्पादों को बेहतर ढंग से बेचने में मदद करेगा और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु परियोजना के उचित पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है।
- पर्यटन से उत्पन्न आय का उपयोग कला, नृत्य और लोकगीतों के जातीय रूपों के संरक्षण में किया जा सकता है। यह ग्रामीण लोगों के हितों की रक्षा करेगा तथा घरों से मीलों दूर जाकर आजीविका कमाने के उनके दबाव को कम करेगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. विकास की पहल और पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव से परवर्तीय पारस्थितिकी तंत्र को कैसे बहाल किया जा सकता है? (मुख्य परीक्षा-2019)

प्रश्न. जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य पर्यटन के कारण अपनी पारस्थितिकी वहन क्षमता की सीमा तक पहुँच रहे हैं। समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिये। (मुख्य परीक्षा- 2015)

स्रोत: द हिंदू

बाल विवाह रोकने हेतु ओडिशा की पहल

प्रलिमिंस के लिये:

अद्विका, बाल विवाह रोकथाम (संशोधन) अधियक 2021

मेन्स के लिये:

भारत में न्यूनतम विवाह योग्य आयु में वृद्धि, बाल विवाह संबंधी मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

ओडिशा पछिले 4-5 वर्षों से [बाल विवाह](#) के संबंध में सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन लाने हेतु दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपना रहा है।

- ओडिशा ने बाल विवाह की व्यापकता में समग्र गरिब दर की है; राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के 21.3% से [NFHS- 5](#) में 20.5% तक।

ओडिशा बाल विवाह की समस्या से कैसे नपिट रहा है?

- राज्य ने बाल विवाह से नपिटने के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्कूलों और गाँवों में लड़कियों की अनुपस्थिति पर नज़र रखना, परामर्श देना तथा 10 से 19 आयु वर्ग की लड़कियों को लक्षित करने वाली सभी योजनाओं को एकीकृत करने के लिये "अद्विका" (Advika) नामक मंच का उपयोग करना शामिल है।
- इसने गाँवों को बाल-विवाह मुक्त घोषित करने के लिये दशा-नरिदेश तथा विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों हेतु मौद्रिक प्रोत्साहन भी जारी किये हैं।
 - बाल विवाह को रोकने के दृष्टिकोण अलग-अलग ज़िलों में भिन्न होते हैं, जिनमें से कुछ कशिरियों का डेटाबेस तैयार करते हैं और अन्य सभी विवाहों में [आधार संख्या](#) को अनिवार्य बनाते हैं।
 - इस समस्या से नपिटने हेतु विभिन्न ज़िलों ने अपने तरीके पेश किये हैं, जैसे कबिल विवाह के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु स्थानीय उत्सव में [कतुथक](#) प्रदर्शन को शामिल करना।
- विशेष रूप से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियाँ जो ड्रॉपआउट हैं और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में बने रहने के साथ समुदाय से जुड़े रहने पर ज़ोर दिया जाता है।
- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के माता-पिता सहित बाल विवाह पर चर्चा करने हेतु ओडिशा पुलिस भी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मासिक

सामुदायिक बैठकें आयोजित करती रही है।

- पुलिस थानों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है ताकि लड़कियाँ पुलिस के पास जाने के लिये खुद को सशक्त महसूस कर सकें।
- बाल विवाह के बारे में जागरूकता के प्रसार हेतु विभिन्न जाति, जनजाति और धार्मिक समूहों के विभिन्न सामुदायिक नेताओं को शामिल किया गया है।

भारत में न्यूनतम विवाह योग्य आयु के संदर्भ में प्रमुख प्रगतः

- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में न्यूनतम विवाह योग्य आयु महिलाओं हेतु 15 वर्ष और पुरुषों के लिये 18 वर्ष थी।
- वर्ष 1978 में सरकार ने इसे बढ़ाकर लड़कियों हेतु 18 और पुरुषों के लिये 21 कर दिया।
- परिवार कानून में सुधार को लेकर वर्ष 2008 में विधि आयोग की रिपोर्ट में शादी के लिये लड़कों और लड़कियों दोनों हेतु 18 वर्ष की एक समान उम्र की सिफारिश की गई।
- वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने सभी धर्मों में महिलाओं हेतु आयु को 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के लिये [बाल विवाह रोकथाम \(संशोधन\) विधियक 2021](#) पेश किया।
 - प्रस्तावित कानून देश में सभी समुदायों पर लागू होगा और एक बार अधिनियमित हो जाने के बाद यह मौजूदा विवाह तथा व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेगा।

बाल विवाह से जुड़े मुद्दे:

- बच्चे के जन्म के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ: बाल विधू अक्सर बच्चे को जन्म देने एवं उसे सुरक्षित रखने हेतु शारीरिक रूप से पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के लिये स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है।
- शिक्षा बाधित: विवाह अक्सर एक लड़की की शिक्षा में बाधक है, जो उसके भविष्य के अवसरों को सीमित कर सकता है और साथ ही [निरिधनता](#) के चक्र में उलझाए रख सकता है।
- सीमित आर्थिक अवसर: बाल विधुओं के पास अक्सर कैरियर बनाने अथवा जीविकोपार्जन के अवसर सीमित होते हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से पति पर निर्भर बना सकता है और इससे [दुर्व्यवहार का जोखिम बना रहता है](#)।
- घरेलू हिंसा: बाल विधुओं को पतियों द्वारा [घरेलू हिंसा](#) का शिकार बनाए जाने की अधिक संभावना होती है, इसका प्रमुख कारण यह है कि सामान्यतः कम उम्र होने के कारण पति द्वारा उन्हें अयोग्य एवं हीन आँका जाता है।
- बाल विवाह एक लड़की के [मानसिक स्वास्थ्य](#) को भी काफी प्रभावित करता है, जिस कारण उसे अवसाद, चिंता और आत्म-सम्मान में कमी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** बाल विवाह के नुकसान के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह के जोखिम वाली लड़कियों को शिक्षा एवं सहायता प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।
 - **उदाहरण के लिये** अधिक अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले मोबाइल एप विकसित किये जा सकते हैं जो लड़कियों को [सहायता नेटवर्क](#) से जुड़ने में सक्षम बना सकते हैं।
- **धार्मिक और सामुदायिक नेतृत्वकर्त्ताओं को सम्मिलित करना:** धार्मिक और सामुदायिक नेता बाल विवाह को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।
 - उन्हें **बाल विवाह के खिलाफ बोलने** और शिक्षा, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये अपने प्रभाव का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **सफलता की कहानियों पर ध्यान दें:** बाल विवाह के खतरों के बारे में जहाँ जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, वहीं सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है।
 - इसका तात्पर्य उन सफल कार्यक्रमों और पहलों पर उत्सव मनाने से है जिन्होंने बाल विवाह की घटनाओं को कम करने में मदद की है, साथ ही उन लड़कियों की सकारात्मक कहानियों को उजागर करना जो शिक्षा और सशक्तीकरण के माध्यम से गरीबी एवं भेदभाव के चक्र से मुक्त होने में सक्षम हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके क्रियान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिये। (2016).

[स्रोत: द हिंदू](#)

प्रलिमिन्स के लिये:

यर बाज़ार वनियमन, सर्वोच्च न्यायालय, सेबी, SCRA, फ्री-मार्केट इकॉनमी, BSE, NSE

मेन्स के लिये:

शेयर बाज़ार वनियमन और धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा कि निवेशकों को [शेयर बाज़ार की अस्थिरता](#) से बचाने हेतु [भारतीय प्रतभूति और वनियम बोर्ड](#) (Securities and Exchange Board of India- SEBI) तथा सरकार मौजूदा नियामक ढाँचे का नरिमाण करें।

शेयर बाज़ार:

परचिय:

- शेयर बाज़ार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयरों के व्यापार हेतु खरीदारों और बकिरेताओं को एक साथ लाते हैं।
- शेयर बाज़ार एक मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था के घटक हैं क्योंकि नविशक व्यापार और पूंजी के आदान-प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुँच को सक्षम करते हैं।
 - मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें सरकारी वनियमन के हस्तक्षेप के बिना आपूर्ति तथा मांग द्वारा नरिधारित की जाती हैं।
- भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं- [बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज](#) (Bombay Stock Exchange- BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange- NSE)।
- SEBI भारत में प्रतभूति बाज़ार का नियामक है। वह कानूनी ढाँचा नरिधारित करता है और बाज़ार संचालन में रुचि रखने वाली सभी संस्थाओं को वनियमित करता है।
 - प्रतभूति संविदा वनियमन अधिनियम (Securities Contracts Regulation Act- SCRA) ने SEBI को भारत में स्टॉक एक्सचेंजों और फरि कमोडिटी एक्सचेंजों को मान्यता देने तथा वनियमित करने का अधिकार प्रदान किया है; यह कार्य पहले केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था।

नियमन के लिये कानून:

- भारतीय प्रतभूति और वनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (SEBI अधिनियम):
 - यह अधिनियम SEBI को निवेशकों के हितों की रक्षा करने और इसे वनियमित करने के अलावा पूंजी/प्रतभूति बाज़ार के विकास को प्रोत्साहित करने का अधिकार देता है।
 - यह SEBI के कार्यों और शक्तियों का नरिधारण करता है और इसकी संरचना तथा प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- प्रतभूति संविदा (वनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA):
 - यह कानून भारत में प्रतभूति अनुबंधों के नियमन के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
 - इसमें प्रतभूतियों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग, स्टॉक ब्रोकर्स एवं सब-ब्रोकर्स का पंजीकरण तथा वनियमन एवं इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक शामिल है।
- कंपनी अधिनियम, 2013:
 - यह कानून भारत में कंपनियों के नियमन, प्रबंधन और शासन को नरियंत्रित करता है।
 - यह कंपनियों द्वारा जारी किये जाने वाले प्रतभूतियों और अन्य प्रतभूतियों के हस्तांतरण के लिये नियम भी नरिधारित करता है।
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996:
 - यह कानून भारत में डिपॉजिटरी के नियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित प्रतभूतियों के अभौतिकीकरण तथा हस्तांतरण के लिये प्रक्रियाओं को नरिधारित करता है।
- इनसाइडर ट्रेडिंग वनियमन, 2015:
 - ये नियम भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतबिधित करते हैं। इस कार्य में शामिल लोगों के लिये आचार संहिता, खुलासे और उल्लंघन के लिये दंड नरिधारित करते हैं।

बाज़ार की अस्थिरता पर अंकुश लगाने में SEBI की भूमिका:

- SEBI बाज़ार की अस्थिरता को रोकने के लिये हस्तक्षेप नहीं करता है, अतः अधिक अस्थिरता को रोकने के लिये एक्सचेंजों में दो सर्कट फिल्टर होते हैं- पहला ऊपरी या अपर सर्कट और दूसरा नचिला या लोअर सर्कट।
- लेकिन सेबी उन लोगों को नरिदेश जारी कर सकता है जो बाज़ार से जुड़े हैं और स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार एवं नपिटान (Settlement) को वनियमित करने की शक्ति रखते हैं।
- इन शक्तियों का उपयोग करते हुए SEBI स्टॉक एक्सचेंजों को पूरी तरह से या चुनदा रूप से व्यापार रोकने का नरिदेश दे सकता है।
- यह संस्थाओं या व्यक्तियों को प्रतभूतियों को खरीदने, बेचने या व्यवहार करने, बाज़ार से धन जुटाने और बचौलियों या सूचीबद्ध कंपनियों से

जुड़ने पर भी रोक लगा सकता है।

धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय:

- दो प्रमुख प्रकार की धोखाधड़ी- बाज़ार हेर-फेर तथा इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिये सेबी ने वर्ष 1995 में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का नबिध वनियम एवं वर्ष 1992 में इनसाइडर ट्रेडिंग वनियमों का नबिध जारी किया।
 - ये नियम अंदरूनी सूत्रों से प्राप्त जानकारी को धोखाधड़ी के रूप में परभाषित करते हैं और इस तरह की धोखाधड़ी की गतिविधियों को प्रतर्बिधित करता है, साथ ही गलत माध्यम से अर्जति लाभों पर दंड जैसे प्रावधान भी हैं।
 - इन नियमों का उल्लंघन वधिय अपराध हैं जसै धन शोधन नविरण अधनियम, 2002 के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है।
- SEBI ने शेयरों के पर्याप्त अधगिरहण और अधगिरहण वनियमों को अधसूचित किया है ताकयिह सुनश्चिति किया जा सके कअधगिरहण एवं प्रबंधन में परविरतन केवल सार्वजनिक शेयरधारकों को कंपनी से बाहर नकिलने का अवसर देने के बाद ही किया जाए, यदवि चाहते हैं।
 - SEBI और स्टॉक एक्सचेंजों के आदेशों के खिलाफ तीन सदस्यीय प्रतभूति अपीलीय न्यायाधकिरण (SAT) में अपील की जा सकती है।
 - SAT से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन पंजीकृत वदिशी पोर्टफोलियो नविशकों द्वारा उन वदिशी नविशकों को जारी किया जाता है जो खुद को सीधे पंजीकृत कयि बनिा भारतीय शेयर बाज़ार का हसिसा बनना चाहते हैं? (2019)

- (a) जमा प्रमाणपत्र
- (b) वाणज्यिक पत्र
- (c) वचन पत्र
- (d) पार्टसिपिटरी नोट

उत्तर: (d)

स्रोत: द हट्टि

वस्तु एवं सेवा कर परषिद की 49वीं बैठक

प्रलिमिंस के लयि:

GST, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधकिरण, उपकर, अप्रत्यक्ष कर, कर चोरी।

मेन्स के लयि:

वस्तु एवं सेवा कर, इसका महत्त्व और संबंधित मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर परषिद ने हाल ही में अपनी 49वीं बैठक में पूर्व अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत बढ़ती जा रही शकियतों की बढ़ती संख्या को प्रबंधित करने के लयि GST अपीलीय न्यायाधकिरण के नरिमाण पर सहमतजिताई है।

प्रमुख बट्टि

- GST अपीलीय न्यायाधकिरण:
 - इस परषिद ने वविादों के नविरण के लयि **राज्य बेंचों के साथ** एक राष्ट्रीय न्यायाधकिरण तंत्र के नरिमाण को मंजूरी दी है।
 - वविादों की बढ़ती संख्या उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायिक मंचों को प्रभावित कर रही है,अतः न्यायाधकिरण GST शासन के तहत इन वविादों हल करेगा।
 - इस वर्ष के वतित वधियक में न्यायाधकिरण के लयि सक्षम वधियाी प्रावधानों को शामिल किया जा सकता है।

- GST न्यायाधिकरण की नई दिल्ली में एक प्रमुख बेंच और राज्यों में कई बेंच अथवा बोर्ड होंगे। प्रधान बेंच और राज्य बोर्डों में समान प्रतिनिधित्व वाले दो तकनीकी और दो न्यायिक सदस्य होंगे।
- लेकिन सभी चार सदस्य प्रत्येक मामले की सुनवाई में शामिल नहीं होंगे, यह शामिल मामले की सीमा या महत्त्व के आधार पर तय किये जाने की संभावना है।
- **लंबित मुआवज़ा देय राशिका भुगतान:**
 - इसने 16,982 करोड़ रुपए (जून 2022 के लिये) की शेष राशिका भुगतान को मंजूरी दे दी है।
 - इसने दिल्ली, करनाटक, ओडिशा, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित छह राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 16,524 करोड़ रुपए के **GST मुआवज़े** को अंतिम रूप दिया है।
- **कम दंड शुल्क:**
 - इसने 20 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों द्वारा वार्षिक रटिर्न दाखल करने में देरी के लिये कम दंड शुल्क को मंजूरी दी।
 - करदाता, जो तीन वैधानिक रटिर्न दाखल करने में असमर्थ हैं, के लिये परिषद ने एक **एमनेस्टी कार्यक्रम** अपनाया है जिसमें सशर्त छूट या देरी से शुल्क जमा करने पर भी छूट शामिल है।
 - रटिर्न दाखल न करने (Non-Filers) वालों को स्वेच्छा से आगे आने और विलंब शुल्क से राहत प्रदान करके एकमुश्त अपना GST रटिर्न दाखल करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु GST एमनेस्टी योजना शुरू की गई थी।
- **दर परिवर्तन:**
 - पेंसिल शार्पनर, राब (तरल गुड़) जैसी कई वस्तुओं पर GST दर में बदलाव किया गया है।
 - इस परिषद ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सहित किसी भी प्राधिकरण के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने प्रत्येक संस्थानों और केंद्रीय तथा राज्य शैक्षणिक बोर्डों को GST छूट देने का भी निर्णय लिया।
- **कर चोरी रोकना:**
 - परिषद ने पान मसाला और गुटखा उत्पादों पर लगाए जाने वाले मुआवज़ा **उपकर** को यथामूल्य आधार से बदलकर एक वशिष्ट आधार पर लगाने का फैसला किया है।
 - वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर उनके मूलानुसार लगाया जाता है।
 - इससे पहले चरण के राजस्व संग्रह को बढ़ावा मलिंगा।
 - परिषद ने यह भी अनिवार्य किया है कि निर्यात की अनुमति केवल GST अनुपालन का आश्वासन देने वाले गारंटी पत्रों पर दी जाएगी।

GST परिषद:

- **परिचय:**
 - यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
 - यह संशोधन संवधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार, **राष्ट्रपति** द्वारा प्रवर्तित किया गया था।
- **सदस्य:**
 - परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
 - प्रत्येक राज्य, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।
- **कार्य:**
 - संवधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार, परिषद GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सफाई कर सकती है, जैसे कि GST मॉडल कानून के तहत कनि वस्तुओं और सेवाओं को GST के अधीन छूट दी जा सकती है।
 - भारतीय संवधान के अनुच्छेद 279 के साथ-साथ अनुच्छेद 279A देश के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है।
 - वे विशेष रूप से संघ शुल्कों और वस्तुओं पर करों से "शुद्ध आय" की गणना तथा क्रमशः माल और सेवा कर परिषद के गठन से संबंधित हैं।
 - यह GST के **वभिन्न स्लैब दर** पर भी निर्णय लेता है।
 - उदाहरण के लिये मंत्रियों के पैनल की एक अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% GST लगाने का सुझाव दिया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा:

- **परिचय:**
 - GST एक **मूल्यवर्द्धति कर प्रणाली** है, जिसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाता है।
 - यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई, 2017 को 101वें संवधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से भारत में 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ पेश किया गया था।
 - GST में उत्पाद शुल्क, **मूल्यवर्द्धति कर (VAT)**, सेवा कर, लकजरी कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है।
 - यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है और अंतिम खपत स्तर पर लगाया जाता है।
- **GST के तहत कर संरचना:**
 - उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिये केंद्रीय GST
 - वैट, विलासिता कर आदि को कवर करने के लिये राज्य GST
 - अंतरराज्यीय व्यापार को कवर करने के लिये एकीकृत GST (IGST)
 - IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिये एक कर प्रणाली है।
 - इसमें स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये 5%, 12%, 18% और 28% की 4-स्तरीय कर संरचना है।

GST से जुड़े मुद्दे:

- **जटिलता:**
 - भारत में **GST प्रणाली कई कर दरों, छूट और अनुपालन आवश्यकताओं के साथ काफी जटिल है।**
 - यह देश में **सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये एकल अप्रत्यक्ष कर की दर की प्रगति को बाधित करता है।**
- **उच्च कर दरें:**
 - कुछ उद्योग और वस्तुएँ उच्च GST दरों के अधीन हैं, जो **कई उपभोक्ताओं के लिये उन्हें अवहनीय बना सकते हैं।**
 - उदाहरण के लिये **विलासिता की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर 28% है, जो काफी अधिक है।**
 - हालाँकि दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है, **50% वस्तुएँ 18% कर के दायरे में हैं।**
- **अनुपालन भार:**
 - GST व्यवस्था में **रटिर्न दाखिल करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और नियमिती ऑडिट** सहित कई अनुपालन आवश्यकताएँ हैं। यह व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों पर एक भार हो सकता है।
- **तकनीकी मुद्दे:**
 - GST नेटवर्क में तकनीकी गड़बड़ी के कारण रटिर्न दाखिल करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में देरी हुई है।
- **असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव:**
 - असंगठित क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, GST से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।
 - कई छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के लिये नई कर व्यवस्था का अनुपालन करना चुनौतीपूर्ण है।
- **स्पष्टता की कमी:**
 - GST व्यवस्था के कुछ पहलुओं पर अभी भी स्पष्टता की कमी है, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण तथा कर दरों की प्रयोज्यता। स्पष्टता की यह कमी भ्रम एवं विवाद की स्थिति पैदा कर सकती है।

आगे की राह

- **अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना, जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करना और करदाताओं के लिये समर्थन बढ़ाना** इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है।
- तकनीकी समस्याएँ जैसे- **सिस्टम डाउनटाइम, पोर्टल एरर और अन्य गड़बड़ियाँ व्यवसायों के लिये गंभीर व्यवधान पैदा कर सकती हैं।** इन तकनीकी मुद्दों को संबोधित करने से व्यवसायों को GST आवश्यकताओं का अधिक प्रभावी ढंग से अनुपालन करने में मदद मिल सकती है।
- कई छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को GST प्रणाली और इसके प्रभावों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। GST प्रणाली के बारे में **मैगारूकता बढ़ाने और शक्ति करने से अनुपालन में सुधार एवं त्रुटियों को कम करने में मदद मिल सकती है।**
- GST केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच एक सहयोगी प्रयास है तथा इसकी सफलता के लिये उनके बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। संचार एवं समन्वय में सुधार से GST प्रणाली के सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित मर्दों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. छलिका उतरे हुए अनाज़
2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधति और डबिबाबंद मछली
4. वजिजापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

उपर्युक्त मर्दों में से कौन-सी वस्तु/वस्तुएँ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतरगत छूट प्रापत है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्वसिज टैक्स/GST)' के क्रयान्वति कयि जाने का/के सर्वाधकि संभावति लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधकिरणों द्वारा वसूल कयि जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापति करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर वदिशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु इसे सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे नकिट भवषिय में चीन से आगे नकिलने में सक्षम बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतपूर्ति निधि को प्रभावित किया है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (मुख्य परीक्षा, 2020)

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रयान्वति जीएसटी के राजस्व नहितार्थों पर भी टपिपणी कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2019)

प्रश्न. संवधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिये। क्या आपको लगता है कि यह "करों के प्रपाती प्रभाव को दूर करने और वस्तुओं और सेवाओं के लिये सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार प्रदान करने" हेतु पर्याप्त रूप से प्रभावी है? (मुख्य परीक्षा, 2017)

प्रश्न. भारत में माल व सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के मूलाधार की विविधता कीजिये। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2013)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

गहरे समुद्र में खनन और इसके खतरे

प्रलिमिंस के लिये:

गहरे समुद्र में खनन, UNCLOS, समुद्री विज्ञान पर फ्रंटियर्स रपिर्ट, गहरे समुद्री मशिन

मेन्स के लिये:

गहरे समुद्र में खनन और इसके प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

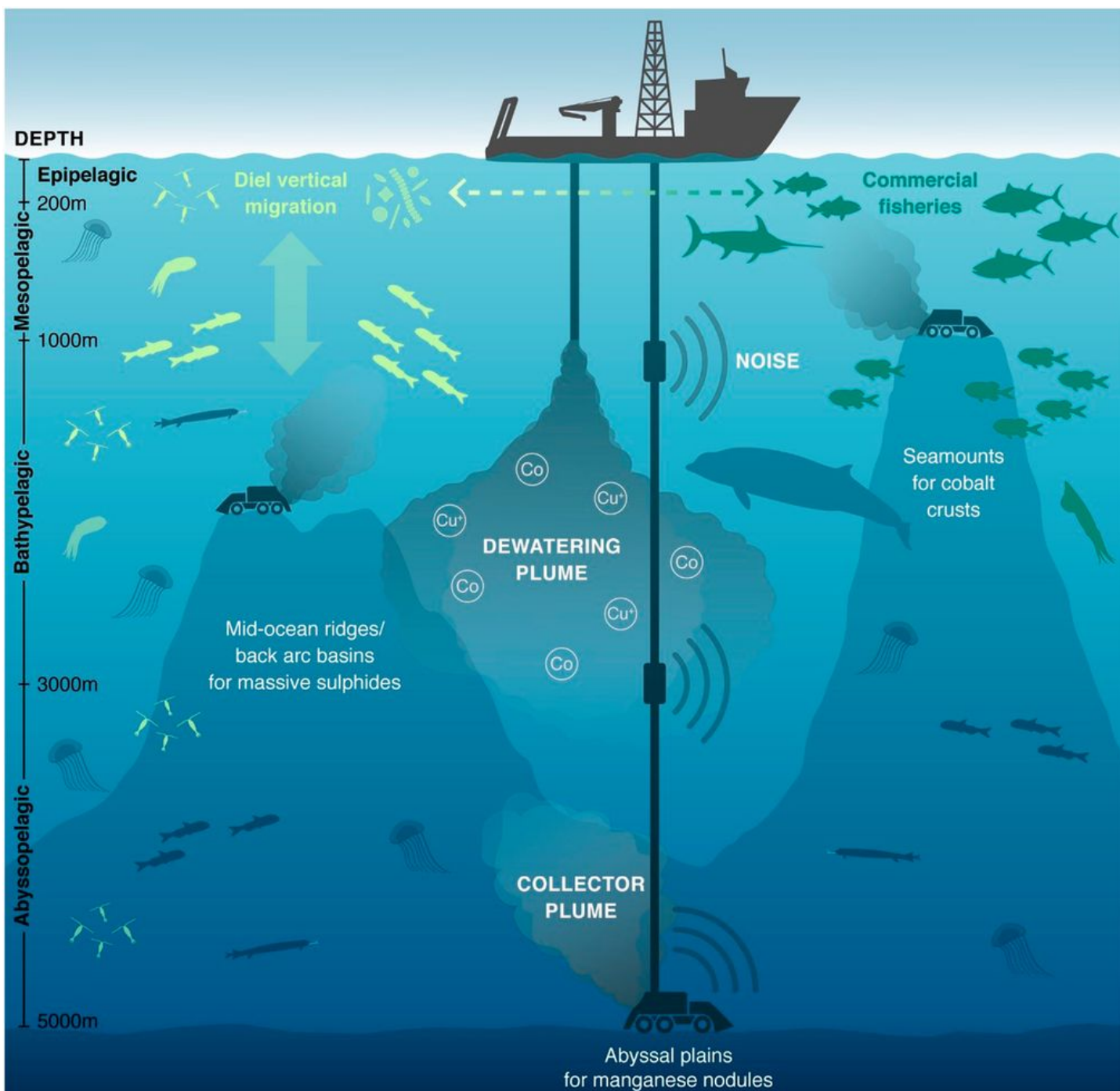
हाल ही के एक अध्ययन ने सुझाव दिया है कि विाणजियकि पैमाने पर गहरे समुद्र तल पर खनन कार्य महासागरों और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे- ब्लू व्हेल और कई डॉल्फिन प्रजातियों को नुकसान पहुँचा सकता है।

- यह मूल्यांकन इन प्रजातियों की रक्षा के लिये नरितर संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर बल देता है।

गहरे समुद्र में खनन:

- परिचय:
- गहरे समुद्र में खनन से तात्पर्य 200 मीटर से नीचे गहरे समुद्र तल से खनजि निकालने की प्रक्रिया से है, जो कुल समुद्री तल के दो-तहाई हिस्से को कवर करता है।
- गहरे समुद्र में खनजि संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिये सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के तहत एक एजेंसी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीबेड वह क्षेत्र है जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है और विश्व के महासागरों के कुल क्षेत्र का लगभग 50% प्रतिनिधित्व करता है।
- ISA ने गहरे समुद्र में खनजि भंडार का पता लगाने के लिये 32 अनुबंध किये हैं। खनजि अन्वेषण का पता लगाने हेतु 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल को अलग रखा गया है।





POTENTIAL EFFECTS

Individuals

- Respiratory distress
- Auditory distress
- Reduced feeding
- Reduced visual communication
- Buoyancy issues
- Toxicity

Populations

- Changes in community composition
- Emigration
- Mortality
- Decreased fitness/reproduction

Ecosystem Services

- Fisheries
- Seafood contamination
- Carbon transport
- Biodiversity

■ शासन:

- ISA को UNCLOS द्वारा 2 वर्षों के भीतर गहरे समुद्र में खनन की रूपरेखा को नयितरति करने वाले नयिमों, वनियिमों और प्रकरियाओं सहित शासन के बुनयिादी ढाँचे को स्थापति करने की आवश्यकता है।
- वफिलता के मामले में **ISA** को कम-से-कम दो वर्ष के अंत तक खनन प्रस्ताव का मूल्यांकन करना चाहिये।
- **11वाँ वार्षिकि डीप सी माइनगि समटि 2023 लंदन, यूनाइटेड कगिडम में आयोजति कथि जाना है।** एजेंडे में "आर्थकि परदृश्य और गहरे समुद्र में खनन के लयि वकिस एवं व्यावसायीकरण से जुडे तकनीकी वकिस" शामिल हैं।

बढती रुचिका कारण:

- **स्थलीय नकिषेपों का कषरण:** तांबा, नकिल, एल्युमीनयिम, मैगनीज़, जस्ता, लथियिम और कोबाल्ट जैसी धातुओं के घटते भंडार के कारण गहरे समुद्र के नकिषेपों की ओर ध्यान केंद्रति हुआ।
 - खनजि संसाधन गहरे प्रशांत और हदि महासागर सहति वभिन्नि गहरे महासागरीय कषेत्रों में पाए जाने वाले **पॉलीमेटेलकि नोड्यूलस** से नकिले जाते हैं।
 - नोड्यूल लगभग **आलू के आकार** के होते हैं और **क्लैरयिन-क्लपिर्टन ज़ोन (CCZ)** में वतिलीय मैदानों में तलछट की सतह पर पाए जाते हैं, जो मध्य प्रशांत महासागर में 4,000 - 5,500 मीटर की गहराई पर 5,000 किलोमीटर (3,100 मील) तक फैला कषेत्र है।
- **बढती मांग:** स्मार्टफोन, पवन टर्बाइन, सौर पैनल और बैटरी का उत्पादन करने के लयि इन धातुओं की मांग भी बढ रही है।

सेटेशयिन (Cetaceans):

- सेटेशयिन वशिष रूप से जलीय स्तनधारी (व्हेल, डॉल्फनि, पोर्पोइज़ आदिसहित) हैं जो सेटेशयिा कर्म का गठन करते हैं। वे दुनयिा भर में महासागरों में और कुछ मीठे पानी के वातावरण में पाए जाते हैं।
- इनका शरीर संकुचति/पतला होता है, कोई बाह्य पश्चपाद नहीं होता है तथा पूँछ दो भागों या कषैतजि ब्लेड के तकिोना नुकीले भाग के रूप में समाप्त होती है।
- अपने सरि के ऊपर स्थति ब्लोहोल्स के माध्यम से साँस लेने के लयि सेटेशयिन को जल की सतह पर आना पड़ता है।

खतरा:

- वाणजियकि पैमाने पर खनन दनि में 24 घंटे संचालति रहने की संभावना है, जसिसे **ध्वनिप्रदूषण** होता है।
 - यह उन आवृत्तयिों के साथ ओवरलैप कर सकता है जनि पर सेटेशयिन संचार करते हैं, जो समुद्री स्तनधारयिों में श्रवण प्रच्छादन और व्यवहार परिवर्तन का कारण बन सकता है।
- खनन वाहनों द्वारा उत्पन्न तलछट का नपिटान आसपास के कषेत्र में समुद्र के तल में प्रजातयिों (बेथेंटकि प्रजाति) को कषतिपिहुँचा सकता है/मार सकता है।
- प्रसंस्करण वाहकिाओं से नकिलने वाले तलछट भी जल के स्तंभ में मैलापन बढा सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि से दूर प्रभाव काफी हद तक अनश्चति हो सकते हैं।

भारत का डीप ओशन मशिन:

- डीप ओशन मशिन गहरे समुद्र तल में खनजिों की खोज और नषिकर्षण के लयि आवश्यक प्रौद्योगकियिों को वकिसति करना चाहता है।
- **पृथ्वी वजिज्ञान मंत्रालय (MoES)** इस बहु-संस्थागत महत्तवाकांक्षी मशिन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा।
- यह एक मानवयुक्त पनडुब्बी (**मत्स्य 6000**) वकिसति करेगा जो वैज्ज्ञानकि सेंसर और उपकरणों के साथ समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक तीन लोगों को ले जा सकती है।
- यह "गहरे समुद्र की वनस्पतयिों और जीवों के जैव-पूरवेक्षण एवं गहरे समुद्र के जैव-संसाधनों के सतत् उपयोग पर अध्ययन" के माध्यम से गहरे समुद्र की जैववविधिता की खोज तथा संरक्षण हेतु तकनीकी नवाचारों को आगे बढाएगा।
- मशिन **अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण (Offshore Ocean Thermal Energy Conversion- OTEC)** संचालति अलवणीकरण संयंत्रों के अध्ययन और वसितृत इंजीनियरगि ढ़ािाइन के माध्यम से समुद्र से ऊर्जा एवं मीठे जल प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास करेगा।

अन्य ब्लू इकॉनमी पहल:

- [सतत् वकिस हेतु ब्लू इकॉनमी पर भारत-नॉर्वे टास्क फोरस](#)
- [सागरमाला परयिोजना](#)
- [ओ-स्मार्ट](#)
- [एकीकृत तटीय कषेत्र परबंधन](#)
- [राष्ट्रीय मत्स्य नीति](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: 'क्षेत्रीय सहयोग के लिये हृदि महासागर रमि संघ (इंडियन ओशन रमि एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन- IOR-ARC)' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2015)

1. इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधपिलाव (आयल स्पलिस) की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रियास्वरूप की गई है।
2. यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- क्षेत्रीय सहयोग के लिये हृदि महासागर रमि संघ (IOR-ARC) हृदि महासागर में रमि (Rim) देशों की एक क्षेत्रीय सहयोग पहल, जसि मार्च 1997 में मॉरीशस में इसके सदस्यों के मध्य आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापति कयिा गया था। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- IOR-ARC एकमात्र अखलि भारतीय महासागर समूह है। इसमें 23 सदस्य देश और 9 डायलॉग पार्टनर हैं।
- इसका उद्देश्य हृदि महासागर रमि क्षेत्र में व्यापार, सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग के लिये एक मंच उपलब्ध कराना है, जो लगभग दो अरब लोगों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- हृदि महासागर रमि सामरिक और कीमती खनजिों, धातुओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों, समुद्री संसाधनों तथा ऊर्जा से समृद्ध है, जो सभी वशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (EEZ), महाद्वीपीय समतल और गहरे समुद्री तल से प्राप्त कयि जा सकते हैं।

अतः वकिल्प D सही है।

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

- वैश्विक महासागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्र तल की खोज और खनन के लिये लाइसेंस प्रदान करता है।
- भारत को अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्र तल खनजि अन्वेषण के लिये लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
- 'दुर्लभ मृदा खनजि' अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जल तल पर मौजूद हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) संयुक्त राष्ट्र का एक नकिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय जल में महासागरों के समुद्री गैर-जीवति संसाधनों की खोज और दोहन को वनियमति करने के लिये स्थापति कयिा गया है। यह गहन समुद्री संसाधनों की खोज एवं दोहन पर वचिर करता है, जो पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है तथा खनन गतिविधियों की नगिरानी करता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- भारत वर्ष 1987 में 'पायनरि इन्वेस्टर' का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश था और नोड्यूल की खोज के लिये भारत को मध्य हृदि महासागर बेसनि (CIOB) में लगभग 5 लाख वर्ग कमी. के क्षेत्र पर अनुमति प्रदान की गई थी। मध्य हृदि महासागर बेसनि में समुद्र तल से पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस की खोज करने के लिये भारत के वशिष अधिकारों को वर्ष 2017 में पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दयिा गया था। **अतः कथन 2 सही है।**
- दुर्लभ मृदा खनजि अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्र तल पर पाए जाते हैं। वभिन्नि महासागरों के समुद्र तल में दुर्लभ-पृथ्वी खनजिों का दुनयिा का सबसे बड़ा अपर्युक्त संग्रह है। **अतः कथन 3 सही है।**

अतः वकिल्प (b) सही है।

?????

प्रश्न. विश्व में संसाधन संकट से निपटने के लिये महासागरों के विभिन्न संसाधनों, जिनका उपयोग किया जा सकता, का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/21-02-2023/print>

